the decennial population Census last conducted in 1981, 66.5 per cent of the total main workers were engaged either as cultivators or agricultural labourers.

Deputation and Ex-Cadre Promotion of J.Es. in C.P.W.D

488. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during calling off the strike of the JEs C.P.W.D. had agreed to take up the cases of deputation and Ex-cadre promotion of the JEs with other departments with a view to reduce stagnation of JEs in CPWD; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes.

(b) In pursuance of the agreement, instructions were issued to all concerned that the names of Junior Engineers should be sponsored liberally for deputation, as and when demands were received from other Departments/Organisations.

Survey of Coal and Lignite in Godavari Valley, U.P.

489. SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to stat:

(a) whether the Geological Survey of India conducted survey for coal and lignite in Godavari Valley (Andhra Pradesh); and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES AND THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b) Yes, Sir. Geological Survey of India (GSI) has recently undertaken stratigraphic drilling in Godavari Valley in parts of Khammam and West-Godavari districts, Andhra Pradesh, to locate coal and lignite bearing formations respectively. Significant coal seams were intersected in three boreholes drilled so far in Khamam districts. Drilling was also taken up recently in tertiary formations of West Godavari district.

Expenditure on Desert Development Programme

490. SHRI BAIKUNTHA NATH SAHU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the amount spent on the desert development programme during the first four years of the Seventh Five Year Plan, State-wise; and

(b) the measures proposed to be adopted to make the desert development scheme a great success?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) Expenditure of Rs. 141.90 crores has been incurred on the programme during the first four years of the Seventh Five Year Plan (upto December 1988). Statewise break-up is given below:—

Sl. No.	State	Expenditure (1985—89 upto Dec. 88) (Rs. in lakhs)
(1)	(2)	(3)
1	Gujarat	658.29
2	Haryana	1130.91
3	Himachal Pradesh	544.94
4	Jammu & Kashmir	752.95
5	Rajasthan	11102.70
	TOTAL	14189.70

(b) The focus of the programme has been sharpened since 1987-88 on activities directly contributing to restoration of ecological balance and arresting of

desertification, taken up on micro-watershed|index catchment approach. Sectoral weightages in expenditure have been prescribed for this purpose and schemes which can be instrumental in achieving these objectives only are now permitted to be taken up under the programme. Government have also set up a National Committee under the chairmanship of Dr. Y. K. Alagh Member, Planning Commission which, among other things, would carry out an appraisal of this programme. Changes, if any, in the programme would be introduced after receipt of the report of the Committee.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण कार्यक्रम हेतु संस्थाओं के लिये मंजूर की गई अनुदान राशि

401. श्री सुशील कुमार पट्टनायक : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं के नाम, पते तथा उन ब्यौरा क्या-क्या हैं, जिन्हें कल्याण मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों हेतु अनुदान राशि प्रदान की गयी है तथा ऐसी प्रत्येक संस्था को कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई;

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, जिन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हुआ है तथा ऐसे व्यक्तियों के कार्यक्रम-वार नाम और पते तथा अन्य ब्यौरे क्या-क्या हैं; और

(ग) क्या इन संस्थाओं के पदधारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते क्या-क्या हैं?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) सूचना अनुबन्ध में दी गयी हैं। [देखिए परिशिष्ट 150, अनुषंग सं० 20]

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या तथा उनके पते के बारे में कार्यक्रम-वार सूचना रखी नहीं गयी है। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किये गये कार्यक्रमों में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये प्रचार, बंधुआ मुक्ति कार्य, औषधालयों, अनाथ तथा बाल कल्याण केन्द्रों, अस्पतालों, उपकेन्द्रों, समाज सेवा केन्द्रों, होस्टलों तथा आवासीय स्कूल शामिल हैं।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के सभी पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं होते हैं। इन व्यक्तियों के नाम और पते इस संबंध में ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

विभिन्न कार्यक्रमों हेतु संस्थाओं के लिये मंजूर की गई अनुदान राशि

402. श्री सुशील कुमार पट्टनायक : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कल्याण निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान, संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के लिये प्रदान की गयी अनुदान राशि का ब्यौरा क्या है तथा उन संस्थाओं के नाम और पते क्या हैं और प्रत्येक को कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रदान की गयी है;

(ख) उपयुक्त संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे केन्द्रों के नाम और पते क्या-क्या हैं तथा उनमें क्रमशः कितने-कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) उन संस्थाओं के लाभभोगियों के नाम और पते क्या-क्या हैं?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।